Naidunia **Date: 08.08.2020**

www.naidunia.com

नई शिक्षा नीति से मनपसंद विषय चुन सकेंगे विद्यार्थी

एसवीवीवी के कुलपति डॉ. धर शामिल हुए ऑनलाइन सम्मेलन में

इंदौर (नईदुनिया रिपोर्टर)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) द्वारा शुक्रवार को आयोजित किए गए ऑनलाइन हायर एजुकेशन सम्मेलन में शहर की श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय (एसवीवीवी) के कुलपति डॉ. उपिंदर धर भी शामिल हुए। डॉ. धर ने बताया कि अब नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को मनपसंद विषय चुनने की आजादी मिलेगी। रिसर्च में गुणवत्ता आएगी और युवाओं को उद्यमी बनने में मदद मिलेगी।

डॉ. उपिंदर धर। ●फाइल फोटो

डॉ. धर ने बताया कि 1986 के बाद से अब देश की शिक्षा नीति बदलने जा रही है। इससे शिक्षा देने का तरीका बदल जाएगा। विद्यार्थी मनपसंद विषय ले सकेंगे। विद्यार्थी जब 12वीं पास होगा तो उसमें ज्यादा समझ रहेगी। जिन विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के बाद उद्यमी बनना है, उनके लिए तीन साल का ग्रेजुएशन होगा और जिन विद्यार्थियों को आगे भी उच्च शिक्षा लेना है उन्हें चार साल का ग्रेजुएशन करना होगा। उन्होंने बताया शिक्षण संस्थानों की ऑटोनॉमी पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यूनिवर्सिटी के साथ अब 300 से ज्यादा कॉलेज नहीं जुड़ेंगे। ऐसा करने से शिक्षण संस्थानों के बीच प्रतियोगिता बढ़ेगी और शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। डॉ. धर ने कहा सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिक्षक लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दें।

आनंद अमृत-2020 आज

श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम 'आनंद अमृत-2020' शनिवार को होगा। इसमें भूटान के पूर्व शिक्षा मंत्री नोरबू वांगचुक और मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य आनंद संस्थान के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में देश-विदेश के शिक्षाविद शामिल होंगे और 30 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धर से विशेष बातचीत

नई शिक्षा नीति से पूरी होंगी जरूरतें

पत्रिका स्पेशल टॉक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. मौजूदा शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। साढ़े तीन दशक बाद आई शिक्षा नीति से उम्मीद है कि पुराना सिस्टम बदलेगा। यह कहना है, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. उपिंदर धर का। प्रो. धर ने मौजूदा व्यवस्था और एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

Q क्या अब कॉलेजों में भी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा?

A नई नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र है। अब तक ज्यादातर रिसर्च विज्ञान से ही जुड़ी रहती थी। इस फाउंडेशन में सभी संकाय की रिसर्च को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे। जो स्तरीय रिसर्च के लिए प्रयास करेंगे निश्चित ही उन्हें अनुदान भी मिलेगा।

Q विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति कितनी फायदेमंद है?

A इसमें विषयों का बंधन खत्म हो रहा है। पहली बार नौवीं से बारहवीं में कोई स्ट्रीम नहीं होगी, यानी बच्चे को पसंद से विषय पढ़ने की आजादी मिलेगी। उच्च शिक्षा में सबसे अच्छा यह होगा कि समय खराब नहीं होगा। किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और कोर्स बीच में छोड़ देता है तो उतनी अवधि का क्रेडिट मिलेगा।

85 कोर्स में प्रवेश

श्री वैष्णव विद्यापीठ में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो चुके हैं। इंस्टी. ऑफ कम्प्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टैक्सटाइल, फॉरेंसिक, लाइफ साइंस, फिजिक्स, कैमिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ, कॉमर्स, पत्रकारिता सहित 14 विभागों के 85 कोर्स शामिल हैं। www.svvv.edu.in पर भी आवेदन किया जा सकता है।

Patrika Date: 06.08.2020

एक्सपर्ट एडवाइज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य सकल नामांकन दर बढ़ाना

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अगर हम इस शिक्षा नीति की बात करें, तो इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को कौशल पर आधारित शिक्षा प्रदान करना है। इस शिक्षा नीति का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन दर बढ़ेगा। इस शिक्षा नीति के तहत पूर्ण पहुंच, इक्विटी और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आधिकाधिक क्षेत्रों में अधिक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (व्यावसायिक शिक्षा सहित) 2030 तक 26.3% (2018) से बढ़कर 50 फीसदी करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों का विकास होगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के संस्थानों का विकास किया जाएगा, हालांकि इसमें मुख्य जोर हर तरह के सार्वजनिक संस्थानों को विकसित करने पर रहेगा। वहीं सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी

डॉ उमेश्वर धर, कुलपति, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

सिस्टम होगा, जिसका काम हर सार्वजनिक संस्थान को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना रहेगा। यदि संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता है, तो वे इस प्रकार के कार्यक्रम चला सकेंगे, जिससे उनका सकल नामांकन अनुपात बढ़े और वे आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ा सकें। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन दर बढ़ाने के लिए इस शिक्षा नीति के तहत सिंगल स्ट्रीम वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए अग्रसर किया जाएगा। वहीं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक और प्रशासनिक तौर पर स्वयत्ता प्रदान की जाएगी। पंद्रह वर्ष में धीरे-धीरे संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और हर शिक्षण संस्थान को स्वायत्ता की ओर बढ़ाया जाएगा। 2025 तक एक विवि से 300 से अधिक कॉलेज संबद्ध नहीं होंगे। वहीं 2035 तक वर्तमान में एक विवि से संबद्ध सभी कॉलेज मान्यता प्राप्त कर स्वायत्त कॉलेज बन जाएंगे। कुल मिलाकर इसके तहत उच्च शिक्षा क्षेत्र को पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा सहित एक उच्च शिक्षा प्रणाली के रूप में तैयार किया जाएगा।